DAINIK JAGRAN, Delhi, 12.7.2017
Page No. 12, Size:(17.08)cms X (11.99)cms.

आधार से जुड़े 67 करोड़ खाते

रविशंकर प्रसाद ने कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले उद्यमियों को सराहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में लगभग 67 करोड़ बैंक खाते अब तक आधार (12 अंकों वाली विशिष्ट पहचान नंबर) से जुड़ चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रसाद कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की ओर से दी जाने वाली आधार सेवाओं पर कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। देश में कुल 110 करोड़ बैंक खाते हैं।

तमाम सेवाएं मुहैया कराने वाले ग्रामीण उद्यमियों के योगदान की सराहना करते हुए प्रसाद ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटरों की ओर से 22 करोड़ आधार नामांकन किए गए हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने ऐसे उद्यमियों से अपील की कि वे नामांकन करने वाली अन्य एजेंसियों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा से कतई नहीं घबराएं। सीएससी का कारोबारी मॉडल लगातार बेहतर होता रहेगा, क्योंकि और अधिक सरकारी विभाग गांवों में नई सेवाओं व रकीगों को पहुंचाने के लिए इन सेंटरों का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इन सीएससी में 10 लाख लोग काम करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी 4-5 वर्षों में यह संख्या बढ़कर एक करोड़ तक पहुंच सकती है, क्योंकि सीएससी की ओर से प्रदान की जाने वाली नई सेवाओं ने इनकी उपयोगिता और बढ़ा दी है।

सुविधा

- नई सेवाओं के लिए बढ़ेगा सीएससी का इस्तेमाल
- आधार सेवाओं पर कार्यशाला का प्रसाद ने किया शुभारंभ

आधार पूरी तरह सुरक्षित

रविशंकर प्रसाद ने आधार को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए कहा कि यह किसी व्यक्ति की न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है। इसमें व्यक्ति की शैक्षिक पृष्ठभूमि, चिकित्सा इतिहास, आमदनी, धर्म या जाति से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी जाती। उन्होंने सीएससी को आगाह किया कि लोगों के डाटा को संभालते समय सावधानी बरतें और किसी भी सूरत में लोगों की बायोमीट्रिक जानकारी नहीं दें।

सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में : रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर अभी 300 सेवाएं दे रहे हैं। इनमें जीएसटी से लेकर डिजिटल भुगतान के लिए प्रशिक्षण शामिल है। जन धन खातों को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ने के चलते यह सुनिश्चित हो गया है कि सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहुंचे। इस पहल से सरकारी खजाने को 50,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। डिजिटल इंडिया अभियान ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब के लिए भेजा जाने वाला हर सौ रुपया सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचता है। कभी राजीव गांधी ने कहा था कि हम दिल्ली से एक रुपये भेजते हैं और गांवों तक इसमें से 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं।